राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

RNI NO. UPHIN/2016/69847

आपरेशन टाइम्स

webportal-www.operatintimes.com, | E-mail:operationtimeslko@gmail.com

वर्षः 10 | अंकः 46 | लखनऊ, बुधवार 14 अगस्त 2024 | पृष्ठ : 04 | मूल्य 2:00 रूपये



कांग्रेस का 22 को देशव्यापी विरोध–प्रदर्शन का ऐलान

नयी दिल्ली,(एजेंसी)। हिंडनबर्ग के आरोपों पर बढ़ते विवाद के बीच कांग्रेस ने मंगलवार को घोषणा की कि वह 22 अगस्त को सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच के इस्तीफे और अडानी मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग को लेकर देशव्यापी आंदोलन करेगी। यह घोषणा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा सभी महासचिवों, राज्य इकाई प्रमुखों और एआईसीसी के राज्य प्रभारियों के साथ बैठक के बाद की गई, क्योंकि पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों के लिए तैयार हो रही है, जिसमें संगठनात्मक मामलों और चुनाव की तैयारियों के लिए राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। एआईसीसी महासचिव एवं सांसद केसी वेणुगोपाल ने बैठक के बाद कहा कि 22 अगस्त को पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक आंदोलन होगा। हम हर राज्य की राजधानी में प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर का घेराव करेंगे और सेबी चेयरमैन को पद से हटाने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि आज हमने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिवों, प्रभारियों और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक बुलाई। इस बैठक में देश में हो रहे सबसे बड़े घोटालों में से एक हिंडनबर्ग घोटाले, अडानी और सेबी से जुड़े घोटाले पर चर्चा हुई। वेणुगोपाल ने कहा कि हमने सर्वसम्मति से इस मुद्दे पर देशव्यापी आंदोलन करने का फैसला किया है, जिसमें दो मांगें हैं, एक अडानी महाघोटाले की जेपीसी जांच, जिसमें प्रधानमंत्री पूरी तरह से शामिल हैं और जिसमें वित्तीय बाजार विनियमन अब गंभीर रूप से समझौता किया गया है।



मुख्यमंत्री योगी का सपा–कांग्रेस पर हमला, बोले...

खटाखट करने वाले गायब हो गए हैं



● खटाखट वाले फिर निकल गए पिकनिक मनाने... सीजन आएगा तो लौटेंगः सीएम योगी

लखनऊ,(एजेंसी)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में संबोधित किया और सपा–कांग्रेस पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पूरी निष्पक्षता से चयन किया है। अब बिना किसी सिफारिश के नियुक्ति पत्र मिल रहा है। यह वही प्रदेश है जहां पहले दंगे होते थे। यहां पहले न बेटी सुरक्षित थी और न व्यापारी। पहले युवाओं के सामने पहचान का संकट था। यह संकट वही लोग पैदा करते थे जो आज फिर आपको बहकाने के लिए आए थे। उन्होंने सपा–कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यही खटाखट है। अब वो गायब हो गए हैं जबकि सीजन आएगा तो फिर लौटेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आज मैं दावे से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश आज सबसे अच्छे ग्रोथ वाला राज्य है। अब युवाओं के सामने पहचान का संकट नहीं है। आप कहीं जाते हैं तो शक की निगाह से नहीं सम्मान की निगाह से देखा जाता है। इसके लिए जनता को भी बधाई। 2017 से पहले कहीं जाने पर कमरा नहीं मिलता था। अब यूपी का नाम बोलने पर सम्मान मिलता है। ऐसे में नव चयनितों की भी जिम्मेदारी बढ़ गई है। 1036 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। इसमें आरक्षण नियमों का पालन हुआ। पहले चाचा भतीजे में लूटने की होड़ लग जाती थी तभी हर नियुक्ति में न्यायालय का हस्तक्षेप होता था। अब बेरोजगारी न्यूनतम स्तर पर है। जब विभिन्न राज्यों के सीएम मिलते हैं तो कहते हैं कि अब यूपी के लोग लौट रहे हैं इसलिए कंपनियों में संकट हो रहा है। हमने सुरक्षा का संकल्प लिया था, जो कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं। लोगों के मन में अन्याय होने का भय पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों के कार्यकाल की तुलना में नौकरियों में 38 फीसदी अधिक ओबीसी का चयन हुआ है। आरक्षण का पूरी तरह से पालन हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब चयन निष्पक्ष हुआ है तो काम भी निष्पक्ष रूप में करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना पूरी करने के लिए आगे आएं। स्वास्थ्य विभाग में सांख्यिकी अधिकारी नियुक्त हो रहे हैं। डाटा एंट्री व्यवस्थित करें ताकि प्रगति तेज हो। आज बिना किसी सिफारिश और लेन–देन के सरकारी नौकरी पाना संभवश सीएम योगी ने कहा कि अब बिना किसी सिफारिश और लेन–देन के उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी प्राप्त करना संभव है। विगत साढ़े सात वर्ष से हमारी सरकार आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा चयन आयोग के द्वारा 2012 से 2017 के बीच 26394 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न हुई थी। इसमें 13469 पदों पर सामान्य, 6966 पदों पर ओबीसी, 5634 पदों पर एससी और 327 पदों पर एसटी वर्ग के युवाओं का चयन हुआ था। इसमें ओबीसी का जो प्रतिशत है, वह केवल 26.38 प्रतिशत था। वहीं हमारी सरकार में उत्तर प्रदेश लोक सेवा चयन आयोग के माध्यम से 46,675 भर्तियां हुईं। इसमें ओबीसी के कुल 17929 अभ्यर्थी चयनित हुए, जिनका प्रतिशत 38.41 है। ओबीसी, एससी और एसटी के प्रतिशत को अगर जोड़ लिया जाए तो डबल इंजन सरकार में 60 प्रतिशत से ज्यादा अभ्यर्थियों का चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा चयन आयोग के माध्यम से हुआ है। आज सभी युवा प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैंः योगी मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से पूर्ववर्ती सरकार (वर्ष 2012 से 2017) के बीच कुल 19312 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, जबकि वर्ष 2017 से 2024 के बीच डबल इंजन सरकार में 42 हजार 409 से अधिक युवाओं को चयन प्रक्रिया से जोड़ा गया है।

सभी युवा अपना योगदान दे रहे हैंः योगी

● मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से पूर्ववर्ती सरकार वर्ष 2012 से 2017 के बीच कुल 19312 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, जबकि वर्ष 2017 से 2024 के बीच डबल इंजन सरकार में 42 हजार 409 से अधिक युवाओं को चयन प्रक्रिया से जोड़ा गया है। हमारी सरकार में संविधान के द्वारा निर्धारित आरक्षण की पूरी व्यवस्था का पालन करते हुए उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया है। आज यह सभी युवा प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि आज प्रदेश में पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है।

हैरिस का साक्षात्कार लेने के लिए तैयार हैं मस्क

वाशिंगटन,(एजेंसी)। अमेरिका के अरबपति उद्यमी एलन मस्क ने मंगलवार को कहा कि वह अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर उपराष्ट्रपति एवं डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस का साक्षात्कार लेने के लिए तैयार हैं। श्री मस्क ने सोमवार को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति एवं रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का एक्स पर साक्षात्कार लिया था। उन्होंने जुलाई में एक्स पर कहा था कि वह श्री ट्रंप की उम्मीदवारी का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा, ष्मुझे एक्स पर सुश्री कमला की भी मेजबानी करके खुशी होगी।" उल्लेखनीय है कि अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडन ने जुलाई में डेमोक्रेटिव पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारी से अपना नाम वापस ले लिया था और सुश्री हैरिस का समर्थन करने की घोषणा की थी।

राम रहीम 21 दिन के पैरोल पर रिहा

चंडीगढ़,(एजेंसी)। बलात्कार और हत्या के आरोप में सजा भुगत रहे सिरसा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम को मंगलवार को 21 दिन के पैरोल पर रिहा कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार जेल से रिहा होने के बाद राम रहीम उत्तर प्रदेश के बागपत आश्रम चला गया। उसे दो साध्वियों के यौन शोषण तथा पत्रकार रामचंदर छत्रपति की हत्या के आरोप में दोषी करार दिए जाने के बाद 20 साल कैद की सजा सुनायी गयी थी और वह रोहतक की सुनारिया जेल में अपनी सजा भुगत रहा है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में राम रहीम को बार–बार पैरोल दिए जाने के खिलाफ शिरोमणि गुरद्वारा प्रबंधक कमिटी की एक याचिका का निबटारा किया है। फरवरी 2022 से राम रहीम को आठ बार पैरोल पर रिहा किया गया है और हर बार लगभग चुनाव के आसपास का समय ही रहा है।



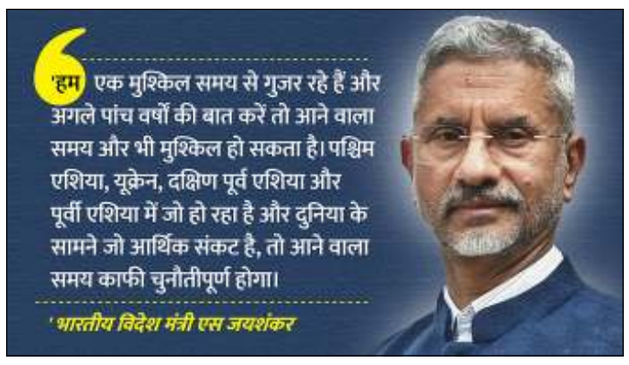
आज शुरू होगी एसएसएलवी –डी3 की उल्टी गिनती

श्रीहरिकोटा,(एजेंसी)। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित होने वाले एसएसएलवी–डी3 के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती बुधवार को शुरू होगी। इसरो के सूत्रों ने बताया कि प्रक्षेपण के लिए उल्टी गिनती कल यानी बुधवार को से शुरू होगी। कुल 175.5 किलोग्राम वजनी इस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह (ईओएस–08) का प्रक्षेपण लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (एसएसएलवी) का उपयोग करके किया जाएगा। यह एसएसएलवी–डी3 तीसर और अंतिम विकासात्मक प्रक्षेपण है और इस चरण में यह माइक्रोसैटेलाइट को लेकर स्वतंत्रता दिवस पर सुबह 09.17 बजे शार रेंज से उड़ान भरेगा। उन्होंने कहा, ष्इस मिशन ने एसएसएलवी विकास परियोजना को पूरा किया है और भारतीय उद्योग तथा एनएसआईएल द्वारा परिचालन मिशनों को सक्षम बनाया है।ष उन्होंने कहा कि ईओएस–08 इसरो का नवीनतम पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ईओएस–08 मिशन के प्राथमिक उद्देश्यों में माइक्रोसैटेलाइट को डिजाइन और विकसित करना, माइक्रोसैटेलाइट बस के साथ संगत पेलोड उपकरण बनाना और भविष्य के परिचालन उपग्रहों के लिए आवश्यक नई तकनीकों को शामिल करना आदि हैं।



भारत–यूएस संबंधों को बनाने में एच1बी वीजा रहा अहम, जयशंकर बोले....

मुश्किल होने जा रहे हालात



नई दिल्ली,(एजेंसी)। जयशंकर ने अपनी बात को समझाते हुए कहा कि श्जब पंडित नेहरू पहली बार अमेरिका दौरे पर गए थे तो उस वक्त अमेरिका में तीन हजार भारतीय मूल के लोग थे, जब इंदिरा गांधी पहली बार अमेरिका गईं तो वहां 30 हजार भारतीय मूल के लोग थे, जब राजीव गांधी गए तो....श। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका के संबंधों को आकार देने में अमेरिका में मौजूद भारतीय मूल के लोगों की अहम भूमिका है। जयशंकर ने ये भी कहा कि दुनिया के मौजूदा हालात को देखते हुए अगले पांच साल का उनका पूर्वानुमान भयावह है। विदेश मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में पूरी दुनिया में अस्थिरता बढ़ सकती है। भारतीय प्रवासी समुदाय की अमेरिका के साथ संबंधों में अहम भूमिका नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि श्शीत युद्ध की समाप्ति के साथ ही एच1बी वीजा ने भारत–अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है।श जयशंकर ने अपनी बात को समझाते हुए कहा कि श्जब पंडित नेहरू पहली बार अमेरिका दौरे पर गए थे तो उस वक्त अमेरिका में तीन हजार भारतीय मूल के लोग थे, जब इंदिरा गांधी पहली बार अमेरिका गईं तो वहां 30 हजार भारतीय मूल के लोग थे, जब राजीव गांधी गए तो अमेरिका में तीन लाख भारतीय मूल के लोग थे और जब नरेंद्र मोदी गए तो यह संख्या बढ़कर 33 लाख से ज्यादा हो चुकी है।श विदेश मंत्री ने कहा कि श्अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों ने अपनी मेहनत, स्किल और प्रतिभा के दम पर अमेरिकी समाज में अपनी जगह बनाई है। लोग किसी भी देश के प्रतिनिधि होते हैं।श श्भारतीय समुदाय ने भारत की छवि को बेहतर कियाश जयशंकर ने कहा कि श्जब अमेरिका में लोग भारतीय प्रवासी समुदाय को देखते हैं, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो लोग कहीं न कहीं उन्हें देखकर भारत के बारे में अपने विचार बनाते हैं।

औरंगाबाद में कार नहर में पलटी, पांच लोगों की मौत

औरंगाबाद,(एजेंसी)। बिहार के औरंगाबाद जिले के दाउदनगर थाना क्षेत्र में मंगलवार को सोन नहर में कार के पलट जाने से पांच लोगों की डूबकर मौत हो गई। दाउदनगर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ऋषि राज ने बताया कि कार पर सवार लोग रोहतास जिले के गुप्ताधाम में दर्शनदृपूजन करने गए थे। वहां से लौटने के क्रम में मंगलवार की सुबह उनकी कार अनियंत्रित हो गई और बारूनदृदाउदनगर नहर रोड स्थित चमन बिगहा गांव के समीप नहर में जा गिरी। नहर में पानी अधिक होने के कारण कार में सवार सभी लोगों की डूबकर मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से कार में सवार सभी मृतकों के शव को बाहर निकाला। श्री ऋषि राज ने बताया कि मृतकों की पहचान पटना जिले के राजीव नगर थाना क्षेत्र निवासी दीपक कुमार (38),कन्हाई राय(37) , रोहित कुमार (12), नारायण चौहान (30) और रवि कुमार (32) के रूप में की गयी है।घटना की सूचना परिजनों को दे दी है।शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है।



जश्न ए आजादी ट्रस्ट और पत्रकार एसोसिएशन ने अमर शहीदों को दी श्रद्धांजलि

कारगिल पार्क में वीर शहीदों की प्रतिमा पर अर्पित किये पुष्प

लखनऊ। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी जश्न ए आजादी ट्रस्ट एवं उत्तर प्रदेश जिला मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन द्वारा देश की आजादी मे प्राण न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों की याद में ष्क शाम वीर शहीदों के नामष कार्यक्रम का शहीद स्मारक स्थल पर आयोजन कर अमर शहीदों की याद में 77 मोमबत्ती और दीप जलाकर पुष्पार्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किये गये,कार्यक्रम मे पर सर्व समाज के प्रतिनिधि और उपस्थित थे, पी.ए.सी. बैंड द्वारा देश भक्ति के गीत प्रस्तुत किए।भारत माता की जय, वन्देमातरम के नारों से पूरा शहीद स्मारक गुंजायमान हो गया। ट्रस्ट के लोगो ने कारगिल पार्क में वीर शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। मुख्य अतिथि व पूर्व उप मुख्यमन्त्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि आजादी के महापर्व में हम विकसित भारत के रुप में दुनिया में अपनी पहचान बनाते जा रहे हैं। जश्न ए आजादी ट्रस्ट के अध्यक्ष मुरलीधर आहूजा ने कहा कि खुशी के पलों में हम अपने वतन की कुर्बानी देने वाले क्रांतिकारियों को कभी ना भूलें।15 अगस्त और 26 जनवरी देश के सबसे बड़े त्योहार हैं।कार्यक्रम संचालन अब्दुल वहीद और वामिक खान ने किया, आए हुए अतिथियों का जुबैर अहमद,मुर्तुजा अली और अब्दुल वहीद ने स्वागत किया, जश्न ए आजादी ट्रस्ट की चेयर पर्सन रजिया नवाज,अध्यक्ष मुरलीधर आहूजा,महामंत्री निगहत खान,कोषाध्यक्ष वामिक खान, संस्थापक सदस्य अब्दुल वहीद, जुबैर अहमद,मुर्तजा अली,सुशील दुबे, अब्दुल अजीज सिद्दीकी,इमरान कुरैशी,फरहा रिजवी,महेश दीक्षित, वेद व्रत बाजपेई,मनीष मिश्रा,देवकी नंदन मिश्रा ,प्रिंस आर्या,अभय अग्रवाल, तौसीफ हुसैन,मौलाना मुश्ताक,परवेज अख्तर,कुदरत उल्ला खान,शाहिद, आफाक मंसूरी,सनी गाँधी,योग गुरु के. डी. मिश्रा,डॉक्टर उमंग खन्ना, डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी,प्रदीप सिंह बब्बू,इमरान कुरेशी, अवधेश सोनकर, रुबी राज सिन्हा, अमरजीत,अब्दुल रसीद, भानुप्रताप सिंह,आरिफ मुकीम, सहित बड़ी संख्या में ट्रस्ट के कार्यकर्ता और आम नागरिक इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।



महिला ग्राम प्रधान ने पुत्रवधू व शिक्षामित्र ब्याहिता पुत्री को पीएम आवास दिलवाया

पूर्णेन्द्र मिश्रा

सीतापुर–१४ अगस्त/उत्तर प्रदेश के सीएम योगी कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार में भ्रष्टाचारी ग्राम प्रधानों पंचायत सचिव के द्वारा ग्राम प्रधान की पुत्रवधू व व्यहिता सरकारी नौकरी कर रही पुत्री को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिलवा दिया गया। जानकारी के अनुसार विकास खण्ड मिश्रित मैं व्याप्त भ्रष्टाचार के चलते ग्राम पंचायत में कागजी विकास दिखाकर सरकारी धन की लूट हो रही है वही ग्राम पंचायत मिश्रित देहात में तैनात ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान की दूषित कार्यशैली के चलते प्रधान मंत्री ग्रामीण आवासो का अधिकाँश लाभ अपात्रों को दिया जा रहा है, वहीं इसी ग्राम पंचायत की महिला प्रधान ने सरकारी सेवा में कार्यरत अपनी पुत्रवधू किरन और ब्याहता पुत्री सुधा को आवास का आवंटन कर दिया गया, ग्राम पंचायत मिश्रित देहात के मजरा ज्ञान सागर की निवासिनी पूर्व अध्यापिका लक्ष्मी देवी वर्तमान में मिश्रित देहात ग्राम पंचायत की प्रधान के द्वारा अपने पुत्र बबलू की पत्नी किरन को प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास का लाभ दिलवाया गया, वहीं ब्याहता पुत्री सुधा का सीतापुर शहर के हबीबपुर मोहल्ले में दो मंजिला आवास है और पति बीरपाल नल कूप विभाग में आपरेटर है और जनपद के काजी कमालपुर क्षेत्र के गांव पचदेउरा के निवासी की पत्नी को ग्राम पंचायत मिश्रित देहात की आवास लाभार्थी सुधा शिक्षा मित्र को आवास लाभार्थी बना दिया गया है, मामला संबंधित पंचायत सचिव और प्रधान की भ्रष्टता का द्योतक है,विदित हो कि ग्राम पंचायत में दर्जनों पात्र व्यक्ति पीएम आवास से वंचित है। ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर उच्चस्तपीय जांच कराकर प्रधान व पंचायत सचिव के विरुद्ध कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने की मांग की गयी है ताकि भ्रष्टाचार का पर्याय ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव के चेहरे बेनकाब हो सके।

सम्पादकीय.....

जलवायु अनुकूल फसलें

यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि जलवायु परिवर्तन के चलते पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों से हमारी खाद्य शृंखला को खतरा पैदा हो गया है। मानसून के पैटर्न में बदलाव, घातक गर्मी की लहरों, समुद्री जलस्तर में वृद्धि तथा आये दिन आने वाले समुद्री तूफान कृषि उत्पादन के लिये संकट पैदा कर रहे हैं। इस बाबत इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की हालिया रिपोर्ट में खतरों के प्रति चेताया गया है। निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन के घातक प्रभावों ने हमारे खेत–खलिहानों में दस्तक दे दी है, जिसका मुकाबला नई रणनीति बनाकर किया जा सकता है। आशंका जतायी जा रही है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से कृषि के क्षेत्र व फसलों की पैदावार में भारी कमी आ सकती है। खासकर छोटे किसानों के लिये यह संकट बड़ा है जो पूरी तरह से मानसूनी वर्षा पर ही निर्भर रहते हैं। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि इन विषम परिस्थितियों में पैदावार को अक्षुण्ण रखने के लिये विशेष उपक्रम किये जाएं। इस दिशा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक दशक पहले जलवायु अनुकूल खेती में नवाचारों को लेकर अपनी परियोजना शुरू की थी। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कई अधिक उपज वाली जलवायु अनुकूल फसलों की किस्मों का शुभारंभ करना इसी कड़ी का हिस्सा है। इस बाबत सरकार का कहना है कि अधिक पैदावार वाली गेहूं के बीजों की किस्मों को सफलता पूर्वक तैयार करने के बाद जलवायु प्रतिरोधी बीजों के साथ धान का रकबा बढ़ाना उसकी प्राथमिकता है। निस्संदेह, इस विकट पर्यावरणीय चुनौती का मुकाबला हम निरंतर स्वदेशी समाधानों के जरिये ही कर सकते हैं। जिसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने की जरूरत महसूस की जा रही है। निस्संदेह, देश में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिये चलाये जा रहे कार्यक्रमों की कोई कमी नहीं है,लेकिन जरूरत इस बात की है कि उपलब्ध संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाए। निस्संदेह, जलवायु परिवर्तन के घातक प्रभावों से कृषि उत्पादन को संरक्षण देने और किसानों के हितों की रक्षा के लिये संसाधनों का बेहतर उपयोग बेहद जरूरी है। इसके साथ ही जल स्रोतों का संरक्षण, वन क्षेत्र की रक्षा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजनाओं के जरिये भूमि की उर्वरता बढ़ाने का उपक्रम भी करने की दरकार है। हमें खेती में कृत्रिम खादों के उपयोग में भी संयम बरतना चाहिये। इसी कड़ी में फसलों के विविधीकरण कार्यक्रम को भी गति देने की आवश्यकता है। इसके लिये किसानों को जागरूक और प्रोत्साहित करने की जरूरत है। यह सुखद है कि देश के कई राज्यों में व्यापक पैमाने पर जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन इस कार्यक्रम को राष्ट्रव्यापी बनाया जाना चाहिये। इस दिशा में प्रोत्साहन योजनाएं किसानों का जैविक खेती अपनाने का मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं। एक तथ्य यह भी कि इस दिशा में नई प्रौद्योगिकी तैयार कर लेने मात्र से ही समस्या का समाधान संभव नहीं है। जरूरत इस बात की है कि वैज्ञानिक अनुसंधानों को खेतों तक पहुंचाया जाए। किसान सहजता से उनका उपयोग करते हुए फसलों के संरक्षण को गति दे सके। दरअसल, किसान को व्यावहारिक रूप से संतुष्ट करना जरूरी भी है कि उसके लिये वास्तव में क्या उपयोगी है। देश में किसानों को जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिये देशव्यापी सहमति बनाने की जरूरत है। इसके लिये आधुनिक अनुसंधान के साथ ही अनुभवजन्य अध्ययन को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सही मायनों में इन प्रयासों को गति देने के लिये अनुसंधान हेतु पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने तथा खेती के लिये उपयोगी निष्कर्षों को किसानों तक पहुंचाने की भी जरूरत है। लगातार भयावह होते परिदृश्य में इस चुनौती को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में शामिल करने की आवश्यकता है। इस हकीकत को जानते हुए कि हम दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं। एक बड़ी आबादी की सामाजिक सुरक्षा के लिये तमाम खाद्यान्न योजनाएं सरकारी अन्न भंडारों के जरिये चलायी जा रही हैं। जिसकी पूर्ति खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाकर ही की जा सकती है। यह तभी संभव है जब हमारी कृषि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों का मुकाबला करने में सक्षम हो।

पेरिस ओलिम्पिक का खट्टा–मीठा समापन

एजेन्सी

> *पदक तालिका में शीर्ष पर खड़े अमेरिका की जनसंख्या भारत के मध्य वर्ग के बराबर भी नहीं है, तो वहीं दूसरे क्रमांक पर भारत से आकार में काफी छोटा जापान है। चीन तीसरे स्थान पर है जो भारत की ही तरह बड़ी आबादी तथा विशाल भूभाग वाला देश है।*

फ्रांस की राजधानी पेरिस में 26 जुलाई को प्रारम्भ हुए 33वें ओलिम्पिक खेलों का समापन रविवार को हुआ। 126 पदकों के साथ अमेरिका (40 स्वर्ण) प्रथम, चीन दूसरे तथा जापान तीसरे क्रमांक पर रहा। 140 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत ने पिछले टोक्यो ओलिम्पिक में कुल 6 मेडल पाये थे, लेकिन उसमें एक गोल्ड था। इस बार भी उसे कुल जमा 6 ही मिले– एक रजत और 5 कांस्य। उसका क्रमांक 71 रहा। छोटे–बड़े 62 देश ऐसे हैं जिन्हें कम से कम एक स्वर्ण पदक अवश्य मिला है। मनु भाकर एकमेव ऐसी खिलाड़ी रहीं जिन्होंने दो पदक पाये। एकमात्र रजत नीरज चोपड़ा को मिला जिन्होंने पिछली प्रतियोगिता में स्वर्ण जीता था। नीरज इस बार अपने परम्परागत प्रतिस्पर्धी अरशद नदीम (पाकिस्तान) से आगे भाला फेंक नहीं पाये। भारत के प्रदर्शन ने फिर साबित कर दिया कि खेल शक्ति बनने के लिये देश का आकार या जनसंख्या जिम्मेदार नहीं बल्कि सरकारों का रवैया, समाज का नजरिया, खिलाड़ियों को मिलने वाला समर्थन व सम्मान, संसाधनों व सुविधाओं की उपलब्धता जैसे तथ्य मुख्य कारक होते हैं। पदक तालिका में शीर्ष पर खड़े अमेरिका की जनसंख्या भारत के मध्य वर्ग के बराबर भी नहीं है, तो वहीं दूसरे क्रमांक पर भारत से आकार में काफी छोटा जापान है। चीन तीसरे स्थान पर है जो भारत की ही तरह बड़ी आबादी तथा विशाल भूभाग वाला देश है। जज्बा– बस यही मायने रखता है। फिर चाहे वह देश का हो या खिलाड़ियों का। भारत में खिलाड़ियों के पास जज्बा और काबिलियत तो है, लेकिन सरकारें निराश करती है। खेलों को गम्भीरता से लेने वाले राज्यों की संख्या गिनाने के लिये एक हाथ की उंगलियां भी काफी हैं। शेष औपचारिकता निभाते हैं और इस क्षेत्र को भी अपनी सियासत का अखाड़ा मानते हैं। सत्ता से जुड़े लोग खेल संगठनों पर काबिज हैं। जिस संगठन की सरकार से जितनी निकटता होगी वह सरकार से उतना ही अनुदान खींच लाता है शासन से सहूलियतें जुटाई जाती हैं, अध्ययन के नाम पर विदेशी दौरे होते हैं, प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के अनुपात में बड़ा सा अधिकारियों का दल होता है। टूर्नामेंट के प्रदर्शनों का विश्लेषण नहीं होता, न ही खर्चों की समीक्षा होती है। ओलिम्पिक हों या कोई और स्पर्धा, लौटने पर खराब प्रदर्शन के लिये थोड़ी–बहुत शिकायतें होती हैं या आलोचना होती है, वह भी खिलाड़ियों की। सरकारें, खेल संगठन एवं अधिकारीगण बच निकलते हैं। ऐसे राज्य जो ढंग के दो खिलाड़ी भी पैदा नहीं करते, वे खेल मंत्रालय से करोड़ों रूपये उठा लाते हैं। जिन कथित पिछड़े राज्यों में खिलाड़ियों को विकसित करने की असीम सम्भावना होती है वहां के खिलाड़ी और संगठन पाई–पाई को तरसते हैं। खैर, ये वे ही पुरानी बातें हैं जो पिछले हर ओलिम्पिक के बाद भारत में कही और दोहराई जाती हैं। इस बार के ओलिम्पिक ने तो यह बताया है कि लोगों में सरकार अगर भेद–भाव और नफरत के बीज बो दे तो उसकी कंटीली शाखाएं हर जगह पर उग आती हैं। इसके कारण खेल का क्षेत्र कैसा विषाक्त बन जाता है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण पेरिस ओलिम्पिक भारत को दिखा गया। देश का प्रतिनिधित्व करने वाली विनेश फोगाट ने एक ही दिन में कुश्ती के तीन मुकाबले जीत लिये थे और स्वर्ण पदक पहुंच में था। अंतिम मुकाबले के पहले उनका वजन 100 ग्राम अधिक पाया गया। बाहर हो गईं। ये वही विनेश हैं जिन्होंने कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इस आरोप के साथ मोर्चा खोला था कि ब्रजभूषण द्वारा उनके समेत कई महिला पहलवानों का उत्पीड़न किया गया है। इसे लेकर देश भर के पहलवानों एवं महिला सम्मान के पक्ष में खड़े लोगों ने दिल्ली और कई जगहों पर प्रदर्शन किये थे। दिल्ली में इनके साथ पुलिस ज्यादतियां भी हुईं। विनेश के साथ साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया आदि विशेष प्रताड़ित किये गये। ब्रजभूषण को उनके गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से इसी प्रकरण के चलते इस बार टिकट नहीं दिया गया था, लेकिन उनके पुत्र करण भूषण सिंह जीत आये। अपने खिलाफ चले आंदोलन की रत्ती भर परवाह न करते हुए ब्रजभूषण पहले भी कह चुके थे–दबदबा है और दबदबा रहेगा।श् 55 किलो केटेगरी में खेलने वाली विनेश को क्यों 50 किलोग्राम श्रेणी में उतारा गया और कैसे दल के पास खान–पान विशेषज्ञों के रहते उनका वजन बढ़ा, इसका जवाब भी उसी दबदबे में छिपा हुआ हो सकता है। उसकी ओर विनेश ने पहले ही अंदेशा जताया था कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है। घोर निराशा में विनेश ने संन्यास की यह कहकर घोषणा कर दी– श्मैं हार गई, कुश्ती जीत गयी।

पेरिस ओलिम्पिक के दौरान हुए इस घटनाक्रम ने भारत से उसकी एक शानदार पहलवान को छीन लिया। ब्रजभूषण के समर्थक और नफरतियों की बांछें खिल गईं तथा वे अपनी ही खिलाड़ी के खिलाफ हो गये। घृणा जो न कराये सो थोड़ा! वैसे नफरत व वर्चस्व भाव से हुई इस घटिया हरकत के बीच प्रेम व खेल भावना की ठंडी बयार भी पेरिस से चलकर भारत और पाकिस्तान तक पहुंची है। नीरज की मां सरोज देवी ने अपने बेटे के रजत को ही गोल्ड बताया और कहा कि श्गोल्ड जिसका है वह भी हमारा बेटा है। ऐसे ही सरहद पार बैठी अरशद की मां रजिया परवीन ने नीरज की जीत के लिये यह कहकर दुआएं की थीं श्वह अरशद का भाई व मित्र होने के नाते उनका बेटा है।

सुधार की खाल में सांप्रदायिकता

राजेंद्र शर्मा

आखिरकार, 1995 के वक्फ कानून में संशोधनों के विधेयक को, फिलहाल एक संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। मोदी सरकार द्वारा प्रस्तावित किसी विधेयक के लिए ऐसे सलूक को, निश्चित रूप से अपवाद ही कहा जाएगा। संसद के पिछले सत्र तक बिना किसी समुचित चर्चा के बल्कि बिना चर्चा के ही, विधेयकों पर संसद से मोहर लगवाने के अपने उतावलेपन के लिए कुख्यात मोदी सरकार का, 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में ही वक्फ विधेयक पर श्विस्तृत और बहुपक्षीयश चर्चा की जरूरत स्वीकार कर लेना और विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने के लिए राजी होना, बेशक हाल के आम चुनाव से निकल कर आई सच्चाइयों को प्रतिबिंबित करता है। इससे तो कोई इंकार ही नहीं कर सकता है कि अब संसद में राजनीतिक ताकतों का संतुलन काफी बदला हुआ है। इस बदले हुए संतुलन का ही संकेतक है कि एक ओर सत्ताधारी भाजपा और दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के बैनर तले विपक्ष की ताकत, लगभग बराबर है और इन हालात में मुख्यतरू तेलूगू देशमङ्ग तथा जनता दल–यूनाइटेड के साथ गठबंधन के बल पर ही, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच पाए हैं। जाहिर है कि सत्ता में होते हुए भी भाजपा इन हालात में, खासतौर पर मोदी के राज के पिछले कार्यकाल की तरह, बहुमत की मनमानी चलाने की उम्मीद नहीं कर सकती है। हालांकि, उसके पास सरकार चलाने के लिए जरूरी बहुमत है, फिर भी विपक्ष की बढ़ी हुई ताकत के सामने, यह बहुमत भी मनमानी चलाने के लिए काफी नहीं है। फिर वक्फ विधेयक के खास मामले में, यह सिर्फ बहुमत के लिए जरूरी संख्या का मामला नहीं रह सकता था। तेलुगू देशम और जनता दल–यूनाइटेड ने बेशक, इस विधेयक पर भी कोई भाजपा से खुद को अलग नहीं कर लिया था। सहयोगी पार्टियों का सत्ता पक्ष के लिए ऐसा कोई धर्मसंकट पैदा करना तो दूर रहा, लोकसभा में जदयू के प्रवक्ता ने औपचारिक रूप से इस विधेयक की पैरवी भी की थी। इसके बावजूद, यह कहना सही नहीं होगा कि ये सहयोगी पार्टियां इस विधेयक का कोई बढ़–चढ़कर समर्थन कर रही थीं। उल्टे प्रस्तावित विधेयक की विपक्ष की प्रबल आलोचनाओं से ये पार्टियां साफ तौर पर असहज नजर आ रही थीं और विधेयक की उनके समर्थन के सारे तर्क, बचाव के तर्क थे। वर्ना उनकी दलीलों के पीछे छुपी बेचैनी आसानी से पढ़ी जा सकती थी। और ऐसा होना, इस संशोधन विधेयक के लाए जाने की पूरी कसरत के अर्थ और मंतव्यों के चलते होना स्वाभाविक ही था, जिनको विपक्ष द्वारा बलपूर्वक रेखांकित किया जा रहा था। पहला सवाल तो यही था कि वक्फ कानून में इस तरह के संशोधनों की आवश्यकता ही क्या थी? संबंधित विधेयक लोकसभा में पेश करते हुए, संसदीय कार्यमंत्री तथा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू तथा सत्ता पक्ष के अन्य वक्ताओं द्वारा भी इसके तमाम दावे किए जाने के बावजूद कि परामर्श की एक विस्तृत प्रक्रिया से गुजर कर उक्त संशोधन प्रस्ताव तैयार किए गए थे, यह सच किसी से छुपा हुआ नहीं था कि उक्त विधेयक किसी भी तरह की पॉपूलर डिमांड पर नहीं लाया गया था। उल्टे मुस्लिम समुदाय, जिसके धार्मिक आचार के हिस्से के तौर पर दान–पुण्य के कार्य के तौर पर, चल–अचल संपत्तियां वक्फ करने की रिवायत आती है और इन संपत्तियों की समुचित व्यवस्था के लिए ही वक्फ कानून बनाया गया है, और मुस्लिम धार्मिक राय के बड़े हिस्से द्वारा इस पूरी कसरत को गहरे संदेह की नजर से ही देखा जा रहा था। ऐसा भी नहीं है कि वक्फ कानून में संशोधन की इस कसरत की आलोचना करने वाले इसका दावा कर रहे हों कि 1995 का वक्फ कानून अपने आप में कोई आदर्श कानून था और उसमें किसी संशोधन या सुधार की कोई गुंजाइश या आवश्यकता ही नहीं थी। यह तो खैर किसी का भी कहना नहीं था कि वक्फ संबंधी सारी व्यवस्था बहुत ही अच्छी तरह से चल रही थी, जिसमें कोई कमजोरियां या खामियां थी ही नहीं। लेकिन, सबसे पहली बात तो यह कि इस पूरी कसरत के पीछे सत्ताधारी भाजपा की नीयत ही संदेह के घेरे में थी। बेशक, सत्ता पक्ष की ओर से गरीब–मुसलमानों की भलाई की चिंता का जमकर दिखावा किया जा रहा था। वर्तमान व्यवस्था में मुस्लिम महिलाओं के निर्णय प्रक्रियाओं से बाहर ही छूटे रहने पर काफी आंसू बहाए जा रहे थे। वक्फ बोर्डों तथा वक्फ से जुड़ी अन्य संस्थाओं के बेशुमार मामलों–मुकदमों में फंसे होने पर बड़ा अफसोस जताया जा रहा था। और वक्फ की संपत्तियों, विशेष रूप से जमीनों का, मुसलमानों की भलाई के लिए ठीक से उपयोग न हो पाने का, खूब रोना रोया जा रहा था। लेकिन, एक ओर जिस तरह के पैट्रनाइजिंग सुर में और दूसरी ओर, मुस्लिम समुदाय की संस्थाओं व समुदाय के नेताओं के प्रति हिकारत के सुर में, ये सारी दलीलें दी जा रही थीं, उनसे कोई समझ सकता था कि इस कसरत के पीछे कम से कम मुसलमानों का भला करने की इच्छा नहीं थी। उल्टे जिस तरह से प्रस्तावित संशोधनों के जरिए, सुधार के नाम पर वास्तव में वक्फ की संपत्तियों पर केंद्र सरकार के नियमनकारी नियंत्रण को उल्लेखनीय तरीके से बढ़ाने की कोशिश की जा रही था, वह किसी से भी छुपा नहीं रहा। वक्फ की संपत्तियों के रिकार्डों को चुस्त–दुरुस्त बनाने के नाम पर, न सिर्फ वक्फ संपत्तियों के लिए एक केंद्रीय रजिस्ट्रेशन व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है बल्कि इन संपत्तियों के संबंध में तमाम जानकारियां नया कानून बनने के छरू महीने के अंदर–अंदर अपलोड किए जाने तथा तमाम नयी वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन उक्त पोर्टल के जरिए ही वक्फ बोर्डों के सामने पेश किए जाने के तकनीकी रूप से उन्नत किए जाने के नजर आने वाले किंतु वास्तव में सब कुछ ज्यादा केंद्रीयकृत करने वाले प्रावधान किए गए हैं। लेकिन, इससे भी ज्यादा समस्यापूर्ण तरीके से पुराने कानून की उस धारा–40 को हटा दिया गया है।



मेष :– मधुरवाणी से संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी। जीविका क्षेत्र में लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। पारिवारिक दायित्वों की समय से पूर्ति हेतु प्रयत्नशील होंगे। जीवन साथी के स्वास्य का ध्यान रखें।

बृषभ मन प्रसन्न व उत्साहित रहेगा। प्रियजनों का सानिध्य प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण कार्य सार्थक होने का योग है। नौकरी का वातावरण सुखद होगा। शिक्षा–प्रतियोगिता की दिशा में परिश्रम तीव्र होगा।

मिथुन :– आर्थिक क्षेत्र में आप कुछ नई योजनाओं को सार्थक करेंगे। कोई व्यक्तिगत संबंध परिवार में विवाद का कारण बन सकता है। प्रणय संबंधों को लेकर मन में चिंता होगी।

कर्क :– पूर्वाग्रहवश मन में किसी प्रकार की शंका न पालें। गलतियों को स्वीकारते हुए सगे–संबंधों में क्षमायाचक बने और शांत भाव से अच्छे कायरे द्वारा उसकी प्राश्चित भी करें।

सिंह :– पुरानी गलतियों से सीख लेते हुए वर्तमान को सुधारें। परिवार को सुव्यवस्थित चलाने में आपका विशेष योगदान होगा। किसी संबंध को लेकर पूरे परिवार के विरोध का सामना करना पड़ेगा।

कन्या :– मन ढ़ेर सारे पूर्वाग्रहों से प्रभावित होगा। पुरानी बातों कों भूलकर वर्तमान के साथ समझौता करें। मन पर नियंतग्रख कर्त्तव्यनिष्ठ बने। जीवनसाथी से वैचारिक मतभेद संभव।

तुला :– आज सकारात्मक सोच को अपनाते हुए जीवन को सही दिशा की ओर केंद्रित करें। पुरानी घटनाओं के स्मरण से मन को कष्ट संभव।

वृश्चिक :– आज परिजनों के सुख–दुख से प्रभावित मन परिवार को एकजुट रखने में केंद्रित होगा।

धनु :– निराशावादी विचारों को त्याग आशावादी बनें। नाजुक संबंधों के बीच भावनात्मक कष्टों को भूल वर्तमान को बेहतर बनायें। परिवार में खुशहाल माहौल रहेगा।

मकर :– मन सुंदर विचारो से सिंचित होगा। धार्मिक व पारंपरिक कायरें की ओर मन केंद्रित होगा। नये कायरें में संलग्नता से लाभ संभव। आलस्य का त्याग करें।

कुंभ :– अपने सुख–दुख को छोड़ परिजनों के सुख के बारे में सोचें। सामान्य दिनचर्या के साथ बीत रहे जीवन में उत्साह का अभाव रहेगा। नयी आकांक्षाएं मन को उद्वेलित करेंगी। पुराने संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी।

मीन :– :– किसी अचल सम्पत्ति को लेने की योजना बन सकती है। कार्यक्षेत्र के किसी सहकर्मी से मतभेद संभव। धनागम की नयी युक्तियों पर मन केंद्रित होगा। जीवन साथी का भावनात्मक स्नेह प्राप्त होगा।

विचाराधीन कैदियों के अधिकारों के हनन का सवाल

के रवींद्रन

> *हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को त्वरित सुनवाई के अधिकार से वंचित करने की कड़ी आलोचना की, जो एक कानूनी लड़ाई में उलझे हुए हैं, जिसने काफी ध्यान आकर्षित किया था।*

जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ कहते हैं कि लोग हमारी अदालतों के काम करने के तरीके से तंग आ चुके हैं, तो न्यायिक प्रणाली पर इससे अधिक गंभीर आरोप और क्या हो सकता है! उनका यह दावा कि न्यायपालिका को केवल न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों के लिए संचालित होने वाली संस्था नहीं होना चाहिए, एक महत्वपूर्ण आलोचना है जो भारत के कानूनी ढांचे के भीतर प्रणालीगत मुद्दों को रेखांकित करती है। यह दृष्टिकोण केवल व्यक्तिगत असंतोष का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि एक अवलोकन है जो समय के साथ सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों और टिप्पणियों में प्रतिध्वनित हुआ है। पिछले सप्ताह सर्वोच्च न्यायालय में सप्ताह भर चलने वाली विशेष लोक अदालत के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में की गई मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की टिप्पणी, अदालत की हालिया कार्रवाइयों और टिप्पणियों के संदर्भ में विशेष रूप से मार्मिक है। हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को त्वरित सुनवाई के अधिकार से वंचित करने की कड़ी आलोचना की, जो एक कानूनी लड़ाई में उलझे हुए हैं, जिसने काफी ध्यान आकर्षित किया था। उनके मामले ने मीडिया में महत्वपूर्ण कवरेज प्राप्त करने के साथ–साथ व्यापक प्रणालीगत मुद्दों का एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया। इसलिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय केवल उनके व्यक्तिगत अधिकारों के बारे में नहीं है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया पर एक व्यापक टिप्पणी भी है। सिसोदिया, बेशक, एक हाई–प्रोफाइल व्यक्ति हैं, लेकिन भारतीय जेलों में बंद लाखों गुमनाम विचाराधीन कैदियों की दुर्दशा पर विचार करें, जो या तो उचित सुनवाई के बिना या जमानत हासिल करने के साधनों के बिना जेल में हैं। उनमें से अधिकांश, अक्सर वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं, तथा खुद को कानूनी अधर में फंसा हुआ पाते हैं। उनके मामले अनिश्चित काल के लिए विलंबित हो जाते हैं। यह स्थिति इस बात की स्पष्ट याद दिलाती है कि न्यायिक प्रणाली की विफलताएं उन लोगों को कैसे प्रभावित करती हैं जिनके पास तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप को आकर्षित करने के लिए संसाधन या बुद्धि की कमी होती है। विचाराधीन कैदियों का मुद्दा कोई नया नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणियों और निर्णयों के कारण इस पर फिर से ध्यान गया है। कई मामलों में, विचाराधीन कैदी अपने मुकदमों की सुनवाई शुरू हुए बिना ही लंबे समय तक जेल में रहते हैं, जो न्याय वितरण प्रणाली में एक महत्वपूर्ण दोष को उजागर करता है। न्यायिक प्रक्रिया में देरी, न्यायिक कर्मियों की कमी और प्रणालीगत अक्षमताओं के कारण यह समस्या और भी बढ़ जाती है, जो मामलों के समय पर निर्णय को रोकती हैं। इस संदर्भ में, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की टिप्पणी सुधार की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता को दर्शाती है। न्यायिक प्रणाली, जैसा कि यह है, अपनी प्रक्रियात्मक देरी और अक्षमताओं के बोझ तले संघर्ष करती हुई प्रतीत होती है। आलोचना केवल व्यक्तिगत अधिकारों के बारे में नहीं है, बल्कि समय पर न्याय देने में प्रणालीगत विफलता के बारे में है। व्यापक निहितार्थ महत्वपूर्ण हैं। वह प्रणालीगत बदलाव की आवश्यकता की ओर इशारा करते हैं, जिसमें न केवल प्रक्रियागत देरी बल्कि अंतर्निहित अक्षमताएं भी शामिल हैं जो प्रणाली को प्रभावित करती हैं। न्यायपालिका की भूमिका केवल निर्णय देना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि न्याय निष्पक्ष और शीघ्रता से दिया जाये। जब प्रणालीगत मुद्दे इस भूमिका को कमजोर करते हैं, तो यह न्यायिक प्रक्रिया में जनता के विश्वास और भरोसे को खत्म कर देता है। न्यायपालिका को एक ऐसी संस्था बनने का प्रयास करना चाहिए जो सभी के लिए न्याय के सिद्धांतों को कायम रखे, न कि केवल एक निकाय जो अपने स्वयं के प्रक्रियात्मक ढांचे के दायरे में काम करता है। ध्यान इस ओर केंद्रित होना चाहिए कि प्रणाली को सभी व्यक्तियों की जरूरतों के लिए अधिक सुलभ, कुशल और उत्तरदायी बनाया जाये, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। निस्संदेह, न्यायिक प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियां जटिल और बहुआयामी हैं। उन्हें तत्काल चिंताओं, जैसे कि विचाराधीन कैदियों की दुर्दशा, और दीर्घकालिक संरचनात्मक मुद्दों, दोनों को संबोधित करने के लिए एक ठोस प्रयास की आवश्यकता है। न्यायिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, न्यायाधीशों और न्यायालय कर्मियों की संख्या बढ़ाने और प्रक्रियात्मक दक्षता बढ़ाने के प्रयास इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इसके अतिरिक्त, देरी और अक्षमताओं के मूल कारणों, जैसे पुरानी प्रक्रियाएं और अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, को संबोधित करना अधिक प्रभावी न्यायिक प्रणाली बनाने में आवश्यक होगा। हाल के आंकड़े स्थिति की गंभीरता को रेखांकित करते हैं।

2023 तक, भारत की जेलों की आबादी का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा विचाराधीन कैदियों का है। यह चौंका देने वाला आंकड़ा एक गंभीर मुद्दे को उजागर करता हैरू भारतीय जेलों में बंद व्यक्तियों का एक बड़ा हिस्सा अभी तक मुकदमे का सामना नहीं कर पाया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2. 5 लाख से अधिक लोग विचाराधीन कैदी थे। इनमें से कई व्यक्ति लंबे समय तक जेल में रहे हैं, अक्सर दोषी पाये जाने पर उन्हें मिलने वाली सजा की अवधि से अधिक। इन विचाराधीन कैदियों की जनसांख्यिकी एक परेशान करने वाला पैटर्न दिखाती है। उनमें से एक महत्वपूर्ण संख्या समाज के वंचित वर्गों से आती है। अध्ययनों से पता चला है कि गरीबी, शिक्षा की कमी और सामाजिक–आर्थिक नुकसान लंबे समय तक हिरासत में रहने से निकटता से जुड़े हुए हैं। कई विचाराधीन कैदी हाशिए के समुदायों से हैं,अनुसूचित जाति और जनजाति, तथा आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि वाले लोग। इन व्यक्तियों के पास अक्सर कानूनी प्रतिनिधित्व या जमानत प्राप्त करने के लिए संसाधन नहीं होते हैं, जिसके कारण उन्हें बिना किसी सुनवाई के लंबे समय तक कारावास में रहना पड़ता है। विचाराधीन कैदियों की समस्या जमानत प्राप्त करने की प्रणालीगत समस्या से और भी जटिल हो जाती है। हजारों लोग इसलिए जेल में नहीं रहते क्योंकि उन्हें दोषी ठहराया गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे जमानत के लिए आवश्यक जमानत राशि का प्रबंध नहीं कर सकते। जमानत देने में असमर्थता अक्सर वित्तीय बाधाओं के कारण होती है, जिससे कई लोगों के लिए अपनी रिहाई सुनिश्चित करना लगभग असंभव हो जाता है। यह वित्तीय बाधा भीड़भाड़ वाली जेलों की समस्या को और बढ़ा देती है और ऐसे व्यक्तियों की लंबे समय तक हिरासत में रहने में योगदान देती है जो अंततरू निर्दोष पाये जा सकते हैं। विचाराधीन कैदियों की दुर्दशा न्यायिक प्रणाली की विफलताओं की एक कठोर याद दिलाती है। प्रणाली की अक्षमता न केवल व्यक्तियों को निष्पक्ष और समय पर सुनवाई के उनके अधिकार से वंचित करती है, बल्कि वंचितता के एक चक्र को भी बनाये रखती है जो असमान रूप से गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों को प्रभावित करती है। वित्तीय बाधाओं के कारण जमानत प्राप्त करने में असमर्थता न्याय के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा को रेखांकित करती है और व्यापक सुधार की आवश्यकता को उजागर करती है।इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। जमानत प्रणाली में सुधार करना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि यह उन लोगों को अनुचित रूप से दंडित न करे जो इसके खर्च वहन नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त, देरी को कम करने और दक्षता बढ़ाने के लिए न्यायिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि न्याय तुरंत दिया जाये। कानूनी सहायता सेवाओं में निवेश और हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए सहायता भी विचाराधीन कैदियों द्वारा सामना की जाने वाली कुछ प्रणालीगत बाधाओं को कम करने में मदद कर सकती है।



वास्तु शास्त्र के अनुसार सावन के महीने में कुछ खास पौधे लगाना शुभ माना जाता है। इन पौधों से न केवल स्वास्थ्य लाभ होते हैं बल्कि ये घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि भी लाते हैं। इन्हें सही दिशा में लगाने से इनके लाभ और भी बढ़ जाते हैं।आइए जानते हैं कौन से पौधे सावन में लगाने चाहिए और इनके क्या फायदे होते हैं:

तुलसी

तुलसी को पवित्र माना जाता है और इसे घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा आती है। यह स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है और इसे औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है।

वास्तु लाभः तुलसी का पौधा घर के पूर्व या उत्तर–पूर्व दिशा में लगाना शुभ होता है। यह धन और समृद्धि लाता है।

बिल्वपत्र

भगवान शिव को प्रिय बिल्वपत्र का पेड़ लगाने से मानसिक शांति मिलती है और स्वास्थ्य लाभ होता है।

वास्तु लाभः इसे घर के आंगन या गार्डन में लगाना अच्छा माना जाता है। यह शुभ फलदायी और सुख–समृद्धि लाता है।

नीम

नीम का पेड़ स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। यह हवा को शुद्ध करता है और कई बीमारियों से बचाता है।

वास्तु लाभः इसे घर के दक्षिण–पूर्व दिशा में लगाना शुभ होता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है।

आंवला

आंवला विटामिन सी का अच्छा स्रोत है और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। यह त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद है।

वास्तु लाभः आंवला का पौधा लगाने से परिवार में सुख–शांति बनी रहती है। इसे घर के पश्चिम दिशा में लगाना शुभ होता है।

अशोक

अशोक का पेड़ दुख और चिंता को दूर करता है। यह घर की खुशहाली और समृद्धि के लिए फायदेमंद होता है।

वास्तु लाभः इसे घर के प्रवेश द्वार के पास या गार्डन में लगाना शुभ होता है। यह शुभता और सकारात्मकता लाता है।

मनी प्लांट

मनी प्लांट को घर में लगाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। यह घर में हरियाली और ताजगी लाता है।

वास्तु लाभः मनी प्लांट को घर के अंदर उत्तर–पूर्व दिशा में लगाना शुभ होता है। यह धन और सुख–समृद्धि लाता है।



मुंह की बदबू, जिसे चिकित्सकीय रूप से हैलिटोसिस कहा जाता है, एक आम समस्या है जो कई कारणों से हो सकती है। मुंह की बदबू एक सामान्य समस्या है, लेकिन इसे सही देखभाल और उपचार से नियंत्रित किया जा सकता है। नियमित मौखिक स्वच्छता बनाए रखना, सही खाद्य पदार्थों का सेवन, और स्वास्थ्य समस्याओं का समय पर इलाज कराना इससे बचने के लिए महत्वपूर्ण है।

मुंह की बदबू के कारण

खराब मौखिक स्वच्छता

–दांतों और जीभ की सही से सफाई न करने से बैक्टीरिया पनप सकते हैं, जो बदबू का कारण बनते हैं।

खाद्य पदार्थ

– प्याज, लहसुन, और मसालेदार भोजन खाने से मुंह में बदबू आ सकती है।

ड्राई माउथ (शुष्क मुंह)

– लार की कमी से मुंह में बैक्टीरिया पनप सकते हैं, जो बदबू पैदा करते हैं। शुष्क मुंह दवाओं, धूम्रपान, या किसी चिकित्सा स्थिति के कारण हो सकता है।

तंबाकू और धूम्रपान

– तंबाकू उत्पादों और धूम्रपान से मुंह में बदबू आ सकती है और मौखिक स्वच्छता खराब हो सकती है।

स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं

– साइनस संक्रमण, गले में संक्रमण, फेफड़ों में संक्रमण, गुर्दे की समस्या, या मधुमेह जैसी स्थितियां बदबू का कारण बन सकती हैं।

डेंटल समस्याएं

– दांतों में सड़न, मसूड़ों की बीमारी, या फंसे हुए खाद्य कण बदबू पैदा कर सकते हैं।

ह की बदबू का इलाज

– दिन में कम से कम दो बार अपने दांतों को ब्रश करें और एक बार फ्लॉस करें।

– जीभ की सफाई करें। नियमित रूप से डेंटिस्ट के पास चेकअप के लिए जाएं।

– पानी अधिक पिएं। शुगर–फ्री गम चबाएं।

– शराब और कैफीन का सेवन सीमित करें।

– प्याज, लहसुन, और मसालेदार भोजन का सेवन सीमित करें।

– तंबाकू उत्पादों का उपयोग बंद करें और धूम्रपान छोड़ें।

– एंटीबैक्टीरियल माउथवॉश का उपयोग करें जो बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। – अगर आपकी बदबू का कारण किसी स्वास्थ्य समस्या से जुड़ा है, तो डॉक्टर से सलाह लें और उचित इलाज कराएं।



विटामिन बी12 की कमी को सुधारने के लिए बीजों का सेवन एक सीधा समाधान हो सकता है, क्योंकि बी12 मुख्यतः पशु उत्पादों में पाया जाता है और अधिकांश बीजों में होता है। हालांकि, कुछ बीजों में अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं जो आपकी संपूर्ण सेहत के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। विटामिन बी12 की कमी के लिए सही विकल्प इस प्रकार हैं –

अलसी बीज

विटामिन बी12 का सीधा स्रोत नहीं है, लेकिन ये ओमेगा–3 फैटी एसिड्स और फाइबर से भरपूर होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकते हैं।

चिया बीज

ये बीज भी विटामिन बी12 का अच्छा स्रोत नहीं हैं, लेकिन इनमें प्रोटीन, फाइबर, और ओमेगा–3 फैटी एसिड्स होते हैं।

हेमप बीज

इन बीजों में प्रोटीन और फैटी एसिड्स होते हैं, हालांकि इनमें भी विटामिन बी12 नहीं होता है।

पंपकिन बीज

इनमें भी विटामिन बी12 नहीं होता है, लेकिन ये मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं।

विटामिन बी12 के लिए अन्य स्रोत

– मांस और मांसाहारी उत्पाद, बीफ, चिकन, और मछली।

– डेयरी उत्पाद दूध, दही, और पनीर।

– अंडेः विशेष रूप से यॉल्क।

– फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थः कुछ अनाज, प्लांट मिल्क, और पोर्टोबल मांस के विकल्प में विटामिन बी12 मिलाया जाता है। यदि आप शाकाहारी हैं या आपके पास विटामिन बी12 के अच्छे स्रोत नहीं हैं, तो विटामिन बी12 सप्लीमेंट्स पर विचार करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। डॉक्टर या पोषण विशेषज्ञ से सलाह लेना हमेशा सबसे अच्छा होता है।



हाल ही में कई राजनेताओं ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के आह्वान का समर्थन किया है। वर्तमान में, ऑस्ट्रेलिया में 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। शोध बताते हैं कि सोशल मीडिया कुछ युवाओं के लिए मददगार हो सकता है, उदाहरण के लिए उन्हें समान विचारधारा वाले साथियों से जोड़ने के संबंध में। हालांकि सोशल मीडिया के इस्तेमाल की उम्र बढ़ाने के बारे में किए गए इस प्रस्तावित परिवर्तन के कई कारण हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण स्क्रीन समय और सोशल मीडिया के उपयोग से बच्चों और युवाओं में अवसाद और चिंता सहित खराब मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है।

सोशल मीडिया से होता है ये नुकसान

सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग या दुरुपयोग मनोवैज्ञानिक भलाई के कई क्षेत्रों को नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे–जैसे आप वयस्कता की ओर बढ़ते हैं, आप तय करते हैं कि आप कौन हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आप किन अंतर्निहित मूल्यों के लिए खड़े हैं और आप जीवन से क्या चाहते हैं। लेकिन क्या सोशल मीडिया इस प्रक्रिया को खतरे में डाल सकता है? एक पहचान विकसित करना लगभग 11 से 15 वर्ष की आयु के बीच, मानव मस्तिष्क साथियों के ध्यान और प्रतिक्रिया के प्रति तेजी से संवेदनशील हो जाता है।

युवा लोग सोशल मीडिया पर हो रहे हैं प्रभावित

परिप्रेक्ष्य, निर्णय, आलोचनात्मक सोच और आत्म–नियंत्रण विकसित करने के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क के हिस्से किसी व्यक्ति के शुरुआती 20 वर्ष की आयु तक पूरी तरह से परिपक्व नहीं होते। किशोर हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। वे साथियों से मान्यता चाहते हैं क्योंकि वे अपने मूल्यों का पता लगाते हैं, अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं और खुद को अभिव्यक्त करना चाहते हैं। लेकिन सोशल मीडिया ने किशोरों के लिए एक मंच प्रदान किया है – विशेष रूप से वे जो एफओएमओ में उच्च हैं, या अलग–थलग हो जाने का डर रखते हैं–इस बात पर ध्यान देने के लिए कि वे कई अन्य लोगों से तुलना कैसे करते हैं, जिनमें नामी प्रभावक भी शामिल हैं। युवा लोग सोशल मीडिया पर जो देखते हैं उसके आधार पर अपनी कई तरह की राय विकसित कर रहे हैं। किसी व्यक्ति की अन्य लोगों की राय के अनुरूप होने की प्रवृत्ति को कभी–कभी बैंडवैगन प्रभाव कहा





जाता है। जबकि सोशल मीडिया की बहुत सारी सामग्री काफी हद तक हानिरहित हो सकती है, सोशल मीडिया–वास्तविक दुनिया की तरह–तेजी से राजनीतिक और ध्रुवीकृत होता जा रहा है, जिसमें विरोधी विचारों के प्रति बहुत कम सहनशीलता है।

सोशल मीडिया के आधार पर बनाई जाती है राय अधिकांश लोग सार्वजनिक रूप से या किसी अज्ञात लोगों के समूह में अपनी वास्तविक राय या मूल्यों को अपने तक ही सीमित रखने को महत्व दे सकते हैं। एक बार जब हम आश्वस्त हो जाते हैं कि हमारे बोलने के तरीके और अंतर्निहित मूल्य प्रणालियों को गलत नहीं समझा जाएगा, तो हम धीरे–ध गिरे खुद को प्रकट करना शुरू कर देते हैं।आजकल हम किशोरों की पूरे जीवन की किताब सार्वजनिक मंच पर खुली देखते हैं, जिससे स्व चिंतन जैसा विचार अनिवार्य रूप से पीछे छूट जाता है। वे न केवल सोशल मीडिया पर जो देखते हैं उसके आधार पर अपनी कई राय विकसित कर रहे हैं, बल्कि वे अक्सर उन्हें तुरंत ऑनलाइन प्रसारित भी करते हैं। बाद में, उन्हें इन विचारों का बचाव करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। किशोरावस्था के लिए हानिकारक हो सकता है सोशल मीडिया 24ध7 आभासी दुनिया में, आज के किशोरों के लिए ऑनलाइन जो कुछ भी देख रहे हैं उसके बारे में गंभीर रूप से सोचने, आत्म–चिंतन करने, अन्वेषण करने और अपना मन बदलने का अवसर कम है। अपनी पहचान बनाने के लिए गलतियां करने, सीमाओं का परीक्षण करने, विचारों का पता लगाने और जानकारी का विश्लेषण करने की बहुत कम गुंजाइश है। ये चिंताएं उन कारणों में से हैं जिनके कारण कई चिकित्सा विशेषज्ञ, माता–पिता और राजनेता समान रूप से बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच को सीमित करना चाहते हैं। जबकि सोशल मीडिया 16 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है, किशोरावस्था का पहला भाग एक बढ़ते बच्चे की पहचान और आत्म–मूल्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण समय है। शोध से पता चला है कि किशोरावस्था में पहचान में गड़बड़ी – अनिवार्य रूप से स्वयं की अस्थिर भावना–वयस्कता में व्यक्तित्व विकारों का एक बड़ा कारण बन सकती है। हम अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं कि सोशल मीडिया पर जीवन पहचान विकसित करने में क्या भूमिका निभाता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम इस क्षेत्र का पता लगाना जारी रखें।

पीएम के नेतृत्व में भारत तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है: सीएम

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर श्हर घर तिरंगाश अभियान के अंतर्गत शतिरंगा यात्रा बाइक रैलीश को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा श्श्प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। इसका मतलब 140 करोड़ भारतवासियों के चेहरे पर खुशहाली लाना है।श्श हर घर तिरंगाश को साढ़े चार करोड़



घरों तक पहुंचाने का संकल्पश अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा श्श्इसके लिए समस्त भारतवासियों को देश की समृद्धि में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एकजुट होकर इस अभियान का हिस्सा बनना होगा।श्श उन्होंने कहा कि श्श्दो वर्ष पहले देश के आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन से जुड़कर हम लोगों ने श्हर घर तिरंगाश के माध्यम से भारत के आन–बान और शान के प्रतीक तिरंगा को हर घर पर लहराया था।श्श योगी ने कहा कि 2022–23 में उत्तर प्रदेश ने पांच करोड़ से अधिक घरों पर तिरंगा लहराने का कीर्तिमान स्थापित किया था और गत वर्ष लगभग साढ़े चार करोड़ घरों पर तिरंगा लहराया था। उन्होंने कहा श्श्प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर इस वर्ष भी उत्तर प्रदेश सरकार ने 'हर घर तिरंगाश को साढ़े चार करोड़ घरों तक पहुंचाने का वृहद संकल्प लिया है।श्श 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा लहराया जाएगाः योगी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा, लखनऊ महानगर की ओर से श्श्राष्ट्र प्रथम की भावनाश्श के साथ यह रैली निकाली गई। मुख्यमंत्री ने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि आज से 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा लहराया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ''भारत माता की जयश्श के नारे के साथ, हाथ में तिरंगा लेकर अपने आवास से पैदल भी चले। उन्होंने राष्ट्रीयता, राष्ट्र प्रथम के भाव और पंच प्राण के संकल्पों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, राज्यसभा सदस्य संजय सेठ, विधान परिषद सदस्य महेंद्र सिंह, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष व विधान परिषद सदस्य प्रांशु दत्त द्विवेदी, विधायक नीरज बोरा, भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी समेत कई कार्यकर्ता आयोजन में शामिल हुए।

रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए तोहफा

24 घंटे उपलब्ध रहेगी फ्री बस सेवा, ड्राइवर–कंडक्टर को भी मिलेगी प्रोत्साहन राशि

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार इस बार भी रक्षाबंधन के पर्व पर बहनों को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। सरकार ने प्रदेश की माताओं और बहनों के लिए बस का सफर फ्री कर दिया है।18 अगस्त की रात 12 बजे से 19 अगस्त की रात 12 बजे तक प्रदेश की महिलाएं रोडवेज की बसों मुफ्त सफर कर सकेंगी। परिवहन राज्यमंत्री दयाशंकर सिंह ने इसके लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने रोडवेज के चालक–परिचालक के लिए भी रक्षाबंधन का तोहफा दिया है। उन्होंने कहा कि चालक–परिचालक जितनी मेहनत करेंगे, उन्हें उतनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। परिवहन राज्यमंत्री ने दिए ये निर्देश बता दें कि रक्षाबंधन के पर्व पर महिलाओं के लिए 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। इस दौरान महिलाएं सिटी बस या फिर परिवहन निगम की किसी भी बस से मुफ्त में यात्रा कर सकती हैं। परिवहन राज्यमंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा है कि रक्षाबंधन पर्व पर अतिरिक्त सेवाएं उपलब्ध कराए। 17 से 22 अगस्त तक आधिकारिक बसों का संचालन कराया जाए, जिससे लोगों को रक्षाबंधन पर्व पर आवागमन में कोई असुविधा न हो। शत प्रतिशत बसों को ऑन रोड किया जाए। सभी अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाए। इस दौरान कोई भी अधिकारी बिना सूचना दिए कार्यस्थल नहीं छोड़ेगा। चालक–परिचालक को मिलेगी इतनी प्रोत्साहन राशि रक्षाबंधन पर रोडवेज के चालक–परिचालक को भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जो भी चालक और परिचालक एक्स्ट्रा समय लगाएगा और जितनी मेहनत करेगा, उसे उतनी ही प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बता दें कि चालक परिचालक द्वारा 18 सौ किमी बस चलाने पर 12 सौ रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इससे अधिक बस संचालन पर 55 पैसे प्रति किमी की दर से अतिरिक्त भुगतान दिया जाएगा। ऐसे ही डिपो व क्षेत्रीय कार्यशाला के तकनीकी कर्मचारी इस अवधि में प्रत्येक दिन उपस्थित होते हैं तो उन्हें एकमुश्त 500 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसी तरह बस स्टेशनों पर तैनात कर्मियों को 5 हजार रुपये प्रति स्टेशन की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।



सेबी प्रमुख के खिलाफ हिंडनबर्ग के आरोप अब सत्ता पक्ष–विपक्ष की बहस से परे: मायावती



लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने मंगलवार को कहा कि सेबी चेयरपर्सन के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोप अब सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के बीच की बहस से परे हैं क्योंकि यह अब केंद्र की साख और विश्वसनीयता को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया मंच श्एक्सश पर लिखा कि पहले अदाणी समूह और अब सेबी चेयरपर्सन पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट फिर से जबरदस्त चर्चा में है। आरोप–प्रत्यारोप का दौर इस हद तक जारी है कि इसे देशहित को प्रभावित करने वाला बताया जा रहा है। अदाणी व सेबी द्वारा सफाई देने के बावजूद मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा बल्कि उबाल पर है। मायावती ने कहा कि वैसे यह मुद्दा अब सत्ता व विपक्ष के वाद–विवाद से परे जा कर केन्द्र की अपनी साख व विश्वसनीयता को प्रभावित कर रहा है, जबकि केन्द्र सरकार को अब तक इसकी जेपीसी या न्यायिक जांच जैसी उच्च–स्तरीय जांच जरूर बैठा देनी चाहिये थी तो यह बेहतर होता।श्श अमेरिकी शोध एवं निवेश कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने शनिवार देर रात जारी अपनी नई रिपोर्ट में कहा था कि बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच और उनके पति धबल बुच ने बरमूडा तथा मॉरीशस में अस्पष्ट विदेशी कोषों में अघोषित निवेश किया था। उसने कहा कि ये वही कोष हैं जिनका कथित तौर पर विनोद अदाणी ने पैसों की हेराफेरी करने तथा समूह की कंपनियों के शेयरों की कीमतें बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया था। विनोद अदाणी, अदाणी समूह के चेयरपर्सन गौतम अदाणी के बड़े भाई हैं। आरोपों के जवाब में बुच दंपति ने रविवार को एक संयुक्त बयान में कहा कि ये निवेश 2015 में किए गए थे, जो 2017 में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति तथा मार्च, 2022 में चेयरपर्सन के रूप में उनकी पदोन्नति से काफी पहले था। ये निवेश '' सिंगापुर में रहने के दौरान निजी तौर पर आम नागरिक की हैसियत से श्श किए गए थे। सेबी में उनकी नियुक्ति के बाद ये कोष ''निष्क्रियश्श हो गए। अदाणी समूह ने भी सेबी प्रमुख के साथ किसी भी तरह के वाणिज्यिक लेन–देन से इनकार किया है। संपत्ति प्रबंधन इकाई 360वन (जिसे पहले आईआईएफएल वेल्थ मैनेजमेंट कहा जाता था) ने अलग से बयान में कहा कि बुच तथा उनके पति धवल बुच का आईपीई–प्लस फंड 1 में निवेश कुल निवेश का 1.5 प्रतिशत से भी कम था और उसने अदाणी समूह के शेयरों में कोई निवेश नहीं किया था।

कोलकाता घटना के बाद बढ़ा आक्रोश, यूपी के 8 हजार से ज्यादा रेजीडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर

लखनऊ। कोलकाता में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना के विरोध में उत्तर प्रदेश के 8 हजार से ज्यादा रेजीडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर है। इस हड़ताल का असर लखनऊ समेत प्रदेश में दिख रहा है। लखनऊ के प्रमुख चिकित्सा संस्थान किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (झ्लळन्) का व्व्क बंद किया गया है। डॉक्टरों ने ट्रामा सेंटर में भी काम करने से मना कर दिया है। उन्होंने नो जस्टिस, नो सर्विस और वी वांट जस्टिस के नारे लगाए गए है। लखनऊ के झ्लळन् का व्व्क बंद बता दें कि कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या की घटना के विरोध में डॉक्टरों का आक्रोश बढ़ रहा है। यूपी में 8 हजार से ज्यादा डाक्टर हड़ताल पर है। सभी डॉक्टरों ने कल रात प्डै–ठभ्न् के गेट से सिंह द्वार तक कैंडल मार्च निकाला था। ठभ्न् में 100 से ज्यादा डाक्टर हड़ताल पर है। वहीं, लखनऊ के झ्लळन् का व्व्क बंद किया गया है। डॉक्टर ट्रामा सेंटर में भी काम नहीं करेंगे। हड़ताल के दौरान रेजिडेंट डॉक्टर व्व्क सेवाएं, नियमित सर्जरी, और अन्य चिकित्सा सेवाओं से खुद को अलग रखेंगे। इसके साथ ही इस हड़ताल का असर अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों पर भी पड़ा है। डॉक्टरों ने कल रात निकाला था कैंडल मार्च सभी डॉक्टरों ने कल रात प्डै–ठभ्न् के गेट से सिंह द्वार तक कैंडल मार्च निकाला था। इसमें झ्लळन् के रेजिडेंट डॉक्टर भी शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने नो जस्टिस, नो सर्विस और वी वांट जस्टिस के नारे लगाए गए है। यह हड़ताल थ्व्क्। के आह्वान पर की जा रही है। इससे यूपी में मेडिकल सेवाओं पर असर पड़ सकता है।



संवेदनशील व्यवस्था बनाने के साथ ही दोषियों पर कार्रवाई भी जरूरी, मायावती ने दी सरकार को सलाह

लखनऊ,(यूएनएस)। कोलकाता में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया है और हड़ताल पर बैठे है। इस मामले पर बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बसपा प्रमुख ने घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद दुखद और शर्मनाक है। साथ ही उन्होंने कहा है कि संवेदनशील व्यवस्था बनाने के साथ ही दोषियों पर कार्रवाई भी जरूरी है। बसपा प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, सरकारी, गैर–सरकारी या जीवन के अन्य किसी भी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान आदि से जुड़ा यह अति–महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दा है जिसको लेकर सभी को जागरूक व सतर्क रहने की जरूरत है, ताकि बंगाल की लेडी डाक्टर जैसी अति–दुखद व शर्मनाक घटनाएं न होने पाएं। मायावती ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि देश भर में होने वाली ऐसी जघन्य घटनाओं की रोकथाम के लिए केन्द्र व राज्य सरकारों को हर स्तर पर समुचित संवेदनशील व्यवस्था करने के साथ–साथ दोषियों के खिलाफ सख्त त्वरित कार्रवाई भी बहुत जरूरी है। बता दें कि कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या की घटना के विरोध में डॉक्टरों का आक्रोश बढ़ रहा है।

लड़के की चाहत ने बनाया बच्चा चोर

लखनऊ,(यूएनएस)। लखनऊ रेलवे स्टेशन से बच्चा चोरी होने के मामले में जीआरपी पुलिस ने आरोपी महिला को धर दबोचा है। 6 महीने के मासूम को पुलिस ने बाराबंकी कोठी थाना क्षेत्र से बरामद किया है। बच्चा कोठी थाना क्षेत्र निवासी महिला के पास था। चोर महिला को गिरफ्तार और बच्चे को बरामद करने वाली टीम का नेतृत्व सीओ जीआरपी विकास पांडेय कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक बच्चे के पिता अनूप जायसवाल महिगांव इटौंजा के रहने वाले हैं। जो कि पत्नी कंचन और अपने 6 महीने के बेटे शनि के साथ उन्नाव से 11 अगस्त को लखनऊ आए थे। शाम 5.30 बजे वह उन्नाव जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे। अनूप यहां पत्नी और बच्चे को बैठाकर किसी परिचित से मिलने चले गए। बच्चा मां के साथ खेल रहा था। तभी आरोपी महिला उसके पास पहुंची। उसने बच्चे को गोद में ले लिया। जीआरपी को पूछताछ करने के बाद पता चला कि आरोपी महिला नीता बिहार की रहने वाली है और उसकी तीन बेटियां हैं। उसने कबूल किया है कि बेटे की चाहत में लड़के की चोरी की थी। पूछताछ में सामने आया कि अनूप जब बच्चा लेकर लखनऊ चला आया था, तो उसकी सास ने कहा कि बच्चा हमें देकर चले जाओ। इसी वजह से पति–पत्नी बच्चे को लेकर लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर ही रुक गए थे। लेकिन अनूप के पास में टिकट खरीदने के लिए रुपए नहीं थे। इसलिए पत्नी और बच्चे को स्टेशन पर छोड़ने के बाद वह रुपये की व्यवस्था करने अपने दोस्त के पास चला गया था। इस बीच बच्चा चोरी हो गया।

मुख्यमंत्री ने तिरंगा यात्रा को दिखाई हरी झंडी, कहा, तिरंगा एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी प्रतीक है

लखनऊ,(यूएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखा दी है। सीएम ने यात्रा का शुभारंभ कर बाइक तिरंगा रैली को रवाना किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि तिरंगा को हर घर पर लहराने का कार्य किया था और मुझे प्रसन्नता है 2022 में उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ से अधिक घरों पर तिरंगा लहराने का कीर्तिमान स्थापित किया था।

गत वर्ष भी आजादी के अमृत कल के प्रथम वर्ष में उत्तर प्रदेश में लगभग 4रू30 करोड़ घरों पर तिरंगा लहराने का कार्य हुआ था और प्रधानमंत्री मोदी के उत्तर प्रदेश सरकार ने हर घर तिरंगा को 4रू30 करोड़ घरों तक पहुंचाने के वृहद संकल्प को हाथ में लिया है। सीएम योगी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अपने सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प के साथ जुड़ते हुए भारत के इस राष्ट्रीय प्रतीक तिरंगा को हर घर तक पहुंचाने के संकल्प में सहभागी बन रहे हैं। पिछले तीन दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर यात्रा किस उत्साह के साथ योग मोर्चा के उत्साही कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन में निकल रहे हैं, आयोजित कर रहे हैं। छात्रों के द्वारा व्यवसायियों के द्वारा तमाम सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के द्वारा इस अवसर पर जो उत्साह दिखाया जा रहा है यह भारत का दर्शन करता है क्योंकि तिरंगा एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी प्रतीक है।

विनोद कुमार रतड़ा लॉयन्स क्लब अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष लेपेल पिन से सम्मानित हुए

लखनऊ,(यूएनएस)। कानपुर रोड हिंद नगर कालोनी स्थित सेंट मीरास इंटर कॉलेज में मंगलवार को ग्रीन कलर डे मनाया गया और इस मौके पर लॉयन्स क्लब लखनऊ प्रीमियर द्वारा नेकी की दीवार लगाई गई। ग्रीन कलर डे पर नर्सरी से कक्षा 2 तक के बच्चे हरे रंग की ड्रेस में सजे हुए थे। बच्चों ने पेड़ पौधों की पेंटिंग बनाई और हरी पत्तियां गले में डाल कर डांस किया। छोटे बच्चे घर से तैयार हो कर आए थे और उन्होंने अपनी ड्रेस के बारे में बताया भी। बच्चे ग्रीन ड्रेस में आने के साथ ही ग्रीन लंच ले कर आए थे। कोई बच्चा मैंगो ट्री बना था तो कोई बच्चा अमरुद के पेड की वेशभूषा में आया था। इस मौके बच्चों और अभिभावकों को तुलसी और गुलदाउदी के पौधे भेंट किए गए। सेंट मीरास इंटर कालेज में ग्रीन डे के मौके पर लॉयन्स क्लब लखनऊ प्रीमियर द्वारा नेकी की दीवार लगाई गई जिसमें जरुरतमंदों को कपड़े भेंट किए गए।

संक्षिप्त समाचार

यूपीएसएससी से चयनित अभ्यर्थियों को सीएम योगी ने बांटे नियुक्ति पत्र

लखनऊ,(यूएनएस)। लोकभवन सभागार में मंगलवार को नियुक्ति पत्र पाकर अभ्यर्थियों के चेहरे खिल उठे। निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की इस भर्ती प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थियों ने सीएम योगी को धन्यवाद कहा। नियुक्ति पत्र पाकर किसी अभ्यर्थी ने अपने पिता के सपने के पूरा होने की बात बताई तो किसी ने अपने परिश्रम की कहानी सुनाई। ज्यादातर अभ्यर्थियों की जुबां पर 2017 के बाद से सरकारी नौकरियों में आई पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए सीएम योगी के प्रति आभार था। योगी सरकार प्रदेश के युवाओं को नौकरी एवं रोजगार से जोड़ने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रही है। स्वयं सीएम योगी अधिकारियों से विभागों में रिक्त हुए पदों की बराबर जनकारी लेते रहते हैं और रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने का समय–समय पर निर्देश भी देते हैं। इसी का परिणाम है कि योगी सरकार विगत साढ़े सात साल में साढ़े छह लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने में सफल रही है। यहीं नहीं, संविदा के माध्यम से 3.75 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी से जोड़ा गया है। साथ ही दो करोड़ लोगों को निजी क्षेत्र,एमएसएम के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इसी का नतीजा है कि 2016 में प्रदेश की जो बेरोजगारी दर 16 प्रतिशत थी, वो घटकर 2.4 रह गई है। सीएम योगी के हाथों नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद राज्य मंडी निरीक्षक के पद पर चयनित हुईं वाराणसी की दीप्ति राय ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी का बहुत–बहुत धन्यवाद। 15 अगस्त से पहले उन्होंने हम लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। दीप्ति ने कहा कि पूरी भर्ती निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से हुई है। मंडी निरीक्षक के पद पर चयनित हुए प्रतापगढ़ के शोभित श्रीवास्तव ने कहा कि पिछली सरकारों में भर्ती परीक्षाएं किसी न किसी वजह से फंस जाती थीं। उनका परिणाम नहीं आ पाता था, लेकिन सीएम योगी के शासनकाल में समय पर परीक्षा और परिणाम आ रहे हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार। मंडी पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्त हुए अंकित गुप्ता का कहना है कि यह भर्ती बिना किसी लेनदेन के संपन्न हुई है। इसकी परीक्षा में पूरी शुचिता एवं निष्पक्षता का पालन किया गया है। उन्होंने सीएम योगी का आभार जताते हुए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया।

शक्ति भवन पर बेरोजगार युवाओं का जोरदार प्रदर्शन

लखनऊ,(यूएनएस)। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शक्ति भवन पर बिजली विभाग में नौकरी की राह देख रहे बेरोजगार युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। मंगलवार सुबह सैकड़ों की संख्या में पहुंचे युवाओं ने अपनी मांगों को लेकर शक्ति भवन का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का कहना है कि विद्युत विभाग में जेई, एई और टेक्निकल गेड 2 समेत अन्य टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पदों पर भर्तियां पहले विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से की जाती थी। लेकिन यूपीपीसीएल की ओर से 7 अगस्त 2024 को एक नोटिस जारी करके ये जानकारी दी गई कि अब सरकार ने उन सभी भर्तियों को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीएसएसएससी) के जरिए कराने की तैयारी में हैं। वहीं युवाओं ने यूपीएसएसएससी पर परीक्षाओं को समय पर संपन्न न कराने और सालों तक लंबित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यूपीएसएसएससी आयोग की ओर से कराई गई 30 से ज्यादा भर्तियां अभी भी लंबित हैं। किसी की परीक्षा नहीं हुई तो किसी का रिजल्ट जारी नहीं हुआ। वहीं विद्युत सेवा आयोग की ओर से पूर्व में कराई गईं सभी भर्तियों की समय से परीक्षा हुई है और समय से भर्तियां संपन्न की जाती रही है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि विद्युत विभाग में जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, टेक्निकल ग्रेड 2 समेत विद्युत् विभाग की अन्य भर्तियों को पहले की तरह विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से ही कराई जाए। साथ ही उन्होंने परीक्षा को ऑफलाइन माध्यम से भी कराने की मांग की। इसके अलावा प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो ऐसे ही बड़ा आंदोलन करके जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे।

एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी एकेटीयू का दीक्षांत समारोह

लखनऊ,(यूएनएस)। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी (एकेटीयू) लखनऊ के 22वें दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए बांग्लादेश का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वहां के हालात से सीख लेना जरूरी है। आने वाले 5 सालों में यूपी के 20 लाख स्टूडेंट्स की स्किल्स को बढ़ाना है। विश्व अनंत संभावना की ओर बढ़ रहा है। एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, आईओटी, डाटा स्ट्रक्चर, रोबोटिक्स के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इंडियन एआई मिशन की शुरुआत मार्च 2024 में की गई है। प्रदेश के सबसे बड़े टेक्निकल विश्वविद्यालय होने के कारण आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है। एकेटीयू एआई के जरिए एग्जाम के पेपर बनाने पर विचार किया जा रहा है। इसे अमल में लाएं, सिर्फ विचार न करें। इस साल 1600 से ज्यादा शोध पत्र छपे हैं। एफिलिएटेड कॉलेजों को नैक रेटिंग मिली पर आप कही पीछे छूट गए। संबद्ध 6 संस्थानों का नाम एनआईआरएफ में लिस्ट में भी है। प्लेसमेंट के लिए प्लेसमेंट ड्राइव के जरिए 6 हजार स्टूडेंट्स को जॉब मिली। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर योग शपथ में लोगों को जोड़ने पर दूसरे स्थान पर रहा। आज भी एकेटीयू द्वारा 100 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किट गई। 5 गांव गोद लेने वाले स्टूडेंट्स जैसे हर घर तिरंगा अभियान मनाया था, इस बार भी भागीदारी करें। तिरंगा ही हमारी शान है, हमारा अभिमान है। आज बांग्लादेश की दशा कैसी है। वहां कैसे घर में ही युद्ध शुरू हो गया। भारत शांतिप्रिय देश हैं, युद्ध नहीं जानता। लोग भले ही शस्त्र चलाएं पर हमारा काम शास्त्र का ज्ञान अर्जित करना है। केरल के वायनाड में ये जो हुआ, उसके पीछे पेड़ काटने की आदत है। हर एक व्यक्ति को मां के नाम से पेड़ लगाने चाहिए। कुलपति प्रो.जेपी पांडेय ने बताया कि 47 हजार 269 स्टूडेंट्स को उपाधि दी गई है। इसमें बीटेक के 24 हजार 721 स्टूडेंट्स और डठ। के 9 हजार 708 शामिल हैं। इनमें कुल 32322 छात्र, 14342 छात्राएं हैं। पदक पाने वाले मेधावियों में 24 छात्र, और 57 छात्राएं हैं। उद्योग जगत से ज्यादा से ज्यादा इंटरैक्शन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय ने स्टूडेंट्स को मेजर डिग्री के साथ माइनर डिग्री लेने के अवसर दिया है। फार्मेसी और आर्किटेक्चर के विषयों को भी माइनर में लेने का अवसर दिया जा रहा है। क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस हैं। विश्वविद्यालय से संबद्ध 24 संस्थानों को नैक अक्रेडिशन हासिल हुआ है।

महिला कांग्रेस ने काले कपड़े पहनकर किया प्रदर्शन

लखनऊ,(यूएनएस)। राजधानी लखनऊ में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया। ये सभी महिलाएं कांग्रेस मुख्यालय से निकल कर विधानसभा की ओर जा रही थीं। पुलिस ने ट्रिपल लेयर की बैरिकेडिंग लगाकर सभी महिलाओं को रोक दिया।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक हर्षित लोचन त्रिपाठी द्वारा हिन्दी दैनिक समाचार पत्र आपरेशन टाइम्स को सांई आफसेट प्रिंटर्स 40 वासुदेव भवन निकट कैसरबाग, लखनऊ (उ0प्र0) से मुद्रित करवाकर, ए-57, (दीनदयालपुरम, तकरोही), इन्दिरा नगर, लखनऊ (उ0प्र0) से प्रकाशित। सम्पादक हर्षित लोचन त्रिपाठी 9336188076 समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा। **कैम्प कार्यालय:** 15/E-2/S-32 श्री सिद्धार्थ मार्केट से0-15 (मुन्शीपुलिया चौराहा) इन्दिरा नगर चौराहा, लखनऊ।